भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2602
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

उत्तर पूर्वी के राज्यों में बीएसएनएल सेवाएं

2602. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि उत्तर पूर्व और अन्य पहाड़ी भू-भाग वाले राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल सेवाएं कनेक्टिविटी, कॉल ड्रॉप और कमजोर सिग्नलों की समस्याओं का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्यों/भू-भागों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) विभिन्न सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) पैरामीटरों के लिए निर्धारित बैंचमार्क के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। पिछली चार तिमाहियों (अर्थात दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 तक समाप्त तिमाहियों) के लिए पूर्वोत्तर और असम एलएसए (लाइसेंस सेवा क्षेत्र) में मोबाइल सेवाओं की निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के अनुसार, बीएसएनएल नेटवर्क से संबंधित अधिकांश क्यूओएस मापदंडों के बेंचमार्क को पूरा कर रहा है।

(ग) और (घ) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार करने के लिए, सरकार डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के अंतर्गत **(i)** देश भर में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए **4**जी सेचुरेशन परियोजना **(ii)** बीओपी/ बीआईपी पर 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं प्रावधान के लिए सीमा चौकी (बीओपी)/सीमा आसूचना

चौकी (बीआईपी) परियोजना **(iii)** सेवा से वंचित गांवों में और राष्ट्रीय राजमार्गों के पास-पास मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) और **(iv)** देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में और मांग के आधार पर गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

*****